(ii) that the delivery is undertain for want of sufficient staff.

(iii) a delivery post office at Baramasia be opened.

(c) Some of the signatories to the petition were contacted by an official of the Post Office on 12-7-88. Though the number of deliveries was reduced from 3 to 2, in accordance with the policy of the Department, there was no irregular delivery or non-delivery of mails. A Delivery Post Office in this locality is not justified.

Functioning of Telephone System in West Bengal

1420. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether complaints about manufacturing of the ten group dialing telephone systems in West Bengal coalfields were received by Government;

(b) if so, whether it is contemplated to replace the old, obsolete telephone exchanges by electronic ones by any specified time;

(c) whether it is a fact that electronic exchange installed at Barabazar, Calcutta has increased the telephone revenue from that exchange by ten fold from Rs. 12 lakn to Rs. 1.20 crore; and

(d) whether Government propose to advance the programme of electronic exchange in West Bengal coalfields by importing equipments?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) Yes, Sir.

(b) Yes, Sir. The Department has a plan to replace the telephone exchanges in Asansol coal belt areas by electronic ones. This includes Asansol, Burnpur, Raniganj, Barakar Neamatpur, Banula, Jamuria, Andal and Rupnarayanpur.

These exchanges are proposed to be replaced for which allotment has already been made and equipment is likely to be supplied during 1989-90.

(c) Yes Sir. There is substantial improvement in the revenue of the Bara Bazar exchanges though increase is not ten fold.

(d) No, Sir. There is no proposal to advance the programme of replacing the exchange with electronic ones by importing equipments. However, the exchange equipment will be of indigenous type supplied by M/s. Indian Telephone Industries.

Electronic Telephone Exchange in Raniganj-Asansol Area

1421. SHRI SAMAR MUKHERJEE: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether Government have sanctioned the conversion of Raniganj-Asansol area telephone exchange into electronic automatic exchange; and

(b) if so, what steps have been taken to implement the scheme and what progress has so far been achieved in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI GIRIDHAR GOMANGO): (a) An allotment of 11,000 lines of local E.10B Electronic Telephone Exchange has been made for Asansol-Raniganj Coal Belt area. It is proposed in this project to replace the existing strowger exchanges by electronic exchanges.

(b) Detailed plans are under preparation for implementing this scheme.

मध्य प्रदेश में बस्तर जिले के लिए सिंचाई/विद्युत परियोजना को स्वीकृति

1422. श्री अजीत जोगी : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य वाले बस्तर जिले के लिए कोई

वृहत सिंचाई/विद्युत योजना स्वीकृति के लिए सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के निर्माण से कितने आदिवासियों के प्रभावित होने की और इसकी डूब में कितने वृक्षों और गावों के आने की संभावना है ;

(ग) डूब के अधीन अनुमानतः कितने मूल्य की भूमि और वन सम्पदा के आने की सभावना है ;

(ध) उक्त परियोजना के निर्माण से डूब में आने वाले प्रभावित आदिवासियों के पुनर्वास के लिए प्रस्तावित प्रबंधों का ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) क्या सरकार ने इन योजनाओं को स्वीकृति देते समय पर्यावरण संबंधी पहलुओं पर भी विचार किया है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार बस्तर जिले की कोई वृहत सिंचाई परियोजना अनुमोदन के लिए लम्बित नहीं पड़ी है । तथापि, मध्य प्रदेश के बस्तर जिले की बोधघाट जल विद्युत परियोजना के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन केन्द्रीय पर्यावरण तथा वन मंत्रालय के अनुमोदन की प्रतीक्षा है ।

(ख) बोधघाट परियोजना से प्रभावित लगभग 8, 875 लोगों की कुल आबादी में से 6,209 व्यक्ति अनुसूचित जाति तथा 733 व्यक्ति अनुसूचित जनजाति के हैं । इस परियोजना के निर्माण से 42 गाव या तो पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से प्रभावित होंगे । यह अनुमान लगाया गया है कि 21 सेंटीमीटर आकार के 22 लाख और इससे अधिक वृक्षों पर इसका प्रभाव पड़ेगा ।

(ग) इसमे जलमग्न होने वाली संभावित भूमि व वनों की लागत इस बात पर निर्भर करेगी कि भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत अन्तिम रूप से कितना मुआवजा दिया जाना है । तथापि, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, 1983 में भूमि के लिए 15.4 करोड़ रु० का प्रावधान किया गया है ।

(घ) परियोजना प्राधिकारियों द्वारा तैयार किए गए पुनर्वास कार्यक्रम के अनुसार प्रत्येक विस्थापित परिवार को बिना किसी प्रकार की लागत के 2 हेक्टेयर (5 एकड) का एक विकसित प्लाट, जोकि कृषि योग्य होगा के साथ-साथ नए पुनर्वास कार्यक्रम के अंतर्गत बिना किसी लागत के एक मकान जिसमें पशुओं को बाधने के लिए पर्याप्त खुला स्थान (500 वर्गमीटर क्षेत्रफल का प्लाट) आदि आवंटित किया जाएगा । जिन लोगों का पुनर्वास किया जाएगा उनको अन्य सुविधाएं यथा स्कूल एवं पीने का पानी आदि भी उपलब्ध कराया जाएगा ।

(ङ) जी हां, । इस प्रकार की स्कीमो का अनुमोदन करने से पूर्व सरकार पर्यावरण की दृष्टि से सभी पहलुओ पर विचार करती है ।

Production of 'Chlorine' Technical/ Tablets

1423. SHRI ASHOK NATH VERMA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether 'chlorine' technical and tablets, one of the effective sources and important measures for desinfecting impure water at house hold level, are in short supply in the country; and

(b) what is the total annual requirement of 'chlorine' technical/ tablets in the country; its actual annual production, names and addresses of manufacturers and price fixed for the same and subsidy; if any, given for its production?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI J. VENGAL RAO): (a) and (b) Disinfecting of water for supply to households is done by Municipalities using liquid chlorine which is easily available in the country. 'Chlorine tablets', which are being manufactured in the country in the